

पृष्ठ 1 का शेष...

एमपीसी बैठक में आरबीआई के तटस्थ रुख की ओर बढ़ने की उम्मीद:मूर्ति नागराजन

बिजनेस रेमेडीज। अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकल उधारी 15.43 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है और शुद्ध उधारी 11.8 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जिसमें राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% है। यह संभव हो सकता है क्योंकि सरकार छोटी बचत से 4.7 लाख रुपये प्राप्त करने और एक साल के ट्रेजरी बिल के माध्यम से 50000 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार लेने का लक्ष्य बना रही है। कुल राजकोषीय घाटा 17.86 लाख करोड़ रुपये है, जिसे विवेकपूर्ण ढंग से वित्तपोषित किया गया है, निधियन आवश्यकता का 66% शुद्ध बाजार उधार है। इससे यह सुनिश्चित होना चाहिए कि अगले वर्ष के लिए कम बाजार उधारी के कारण ब्याज दरों पर कम दबाव है। सीपीआई मुद्रास्फीति के 6% के नीचे आने की उम्मीद को देखते हुए, अगले वित्तीय वर्ष में आरबीआई अब अर्थव्यवस्था में विकास का समर्थन करेगा और केवल मुद्रास्फीति नियंत्रण पर ध्यान केन्द्रित नहीं करेगा। (स्रोत: ब्लूमबर्ग)

इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर लगभग 4% - 4.3% रहने की उम्मीद है। आगामी एमपीसी बैठक में आरबीआई के तटस्थ रुख की ओर बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सीपीआई मुद्रास्फीति प्रक्षेप और उधार कार्यक्रम दोनों प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर हैं। आरबीआई के अब अगले वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 6.5% तक समर्थन देने पर ध्यान केन्द्रित करने की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति सहायक नहीं होने की आशंका है। कम उधार कार्यक्रम के कारण दस साल के बॉन्ड के 7.10% - 7.40% के दायरे में व्यापार करने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट एक अच्छा संतुलित बजट है: श्रीनिवास राव रावुरी

बिजनेस रेमेडीज। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट एक अच्छा संतुलित बजट है, जिसमें राजकोषीय सुझाव, निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ कुछ लोक-उन्मुख कदम भी समाप्त रूप से उठाए गए हैं। राजकोषीय गणित पहले की तरह विष्वक्तीय नजर आ रहा है। सरकार का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वर्ग पर फोकस के साथ समावेशी विकास, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास है। हमारा मानना है कि यह व्यावहारिकता पर टिका विकासोन्मुखी बजट है।

वित्त वर्ष 2024 बजट अमृत काल में भारत के सतत विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है। 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, यह 35,000 करोड़ रुपये के बड़े आवंटन के साथ उर्जा संकमण और अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन पर केंद्रित है। लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन बजट में गहराई तक समाया हुआ है और जलवायु संकट से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। वैश्विक स्तर पर, भारत स्थापित नवीकरणीय उर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है और बजट पवन और सौर जैसे क्षेत्रों में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और बढ़ावा देगा। हरित विकास का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें बैटरी भंडारण के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, नवीकरणीय उर्जा निकासी, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और हरित ऋण नीति शामिल है। रुपये के निवेश के साथ 10,000 करोड़, बजट गोबरधन योजना के माध्यम से एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को उपनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता के तीन केंद्र स्थापित करना सरकार की ओर से एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह आरबीआई स्पेस में कौशल की खार्इ की पाठता है और

अनिल चौधरी, जोन अध्यक्ष, भारत और सीईओ व एमडी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा.लि.

अभिव्य की तकनीक विकसित करने के लिए प्रतिभा का पोषण करता है।

अनिल चौधरी, जोन अध्यक्ष, भारत और सीईओ व एमडी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा.लि. 'इस बजट में लंबी अवधि के विजन, संरचनात्मक सुधार और इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सोशल डेवलपमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। 10 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय भारतीय इकोनॉमी में जारी पॉजिटीव मोमेंटम के लिए काफी उत्साहजनक संकेत है। समावेशी विकास और महिला तथा समाज के कमजोर तबके को सशक्त बनाए जाने से बढ़ती समृद्धि वाले देशों में व्यापक भागीदारी के चले रहे ट्रेंड को और मजबूती मिलेगी। राजकोषीय मोर्चे पर देखा जाए तो नेट बॉरोइंग के 11.8 लाख करोड़ रुपये पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया गया है जो कुल जीडीपी के 5.9 फीसदी के बराबर है। यह पिछले वित्त वर्ष के 6.4 फीसदी की तुलना में बहुत अधिक सुधार को दिखाता है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को घटाकर 4.5 फीसदी के नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। नॉमिनल जीडीपी ग्राइ के 10.3 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं, महंगाई दर के आने वाले महीनों में नीचे आने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दर वर्तमान स्तर के आसपास स्थिर रहेंगे, मजबूत बजट से एमपीसी को महंगाई के सफाई साइड मैनेजमेंट, गोथ मोमेंटम और राजकोषीय स्थिरता को मैनेज करने के लिए थोड़ी गुंजाइश मिल जाएगी। इससे मार्जिन पर उदार रुख की गुंजाइश पैदा हो जाती है। हमें उम्मीद है कि दुनिया के अन्य सेंट्रल बैंकों की तरह आरबीआई भी कैलेंडर वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में वृद्धि का सितारिला रोकने की तरफ बढ़ेगा। हालांकि, ब्याज दर में इजाफे की थोड़ी गुंजाइश फिर भी बनी रह सकती है। लंबी अवधि की ब्याज दरें वर्तमान साइकिल के लिए संभवतः अपने उच्चतम स्तर पर पहले ही पहुंच गई हैं और वर्तमान स्तर पर थोड़े समय के लिए इसमें स्थिरता देखने को मिल सकती है। दिन के दौरान बॉन्ड यील्ड्स में 5-8 बेसिस प्वाइंट्स की नरमी देखने को मिली। वित्त वर्ष 2023-24 के बॉरोइंग शिड्यूल और इस विश्लेषण के साथ इसमें कमी आई है कि राजकोषीय घाटे का करीब 65 फीसदी पूंजीगत व्यय से जुड़ा है। 10 साल के बीचमार्क सरकारी बॉन्ड में दिन के कारोबार के दौरान 5 आधार अंक की नरमी के साथ 7.29 फीसदी के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही थी।

महेंद्र जाजू, सीआईओ (फिक्स इनकम), मिरे एस्टेट इवेस्टमेंट मैनेजर्स

वित्त वर्ष 2024 बजट 'हरित प्रसार' के एक चरण की शुरुआत करता प्रतीत होता है, जो अर्थव्यवस्था को एक सतत विकास मार्ग की ओर ले जाता है। उर्जा दक्षता बढ़ाने और कार्बन की तीव्रता कम करने के लिए विभिन्न पहलों को लागू करने पर ध्यान केन्द्रित करके, यह देश में हरित विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। प्रस्तावित बजट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर हरित रोजगार देना अक्सरों के निर्माण पर जोर देता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का 19,000 करोड़ रुपये का परिव्यय भी हरित विकास और शुद्ध शून्य कार्बन अभिव्य में समर्थन और योगदान देगा। उर्जा परिवर्तन और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान वास्तव में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में देश की मदद करेगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली के लिए माननीय प्रधान मंत्री की दृष्टि के कारण एक जिम्मेदार और उर्जा-सुरक्षित देश बन जाएगा, जिससे देश को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में तेजी आएगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।

डॉ. सतीश कुमार, अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक, एनायस फॉर एन एनजी एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE)

'बजट व्यावहारिक है और देश में हरित गतिशीलता उपनाने को आगे बढ़ाने की दिशा में सही कदम उठाए हैं। ली-आयन कोशिकाओं पर सीमा शुल्क छूट का विस्तार और एलआई-आयन सेल्स के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली आयातित मशीनरी पर सीमा शुल्क को हटाने से लागत में कमी आएगी। आगे बढ़ते हुए, हम निश्चित हैं कि सरकार बैटरी पैक निर्माताओं के लिए एक पीएलआई योजना लाने पर भी विचार करेगी और ईवी क्षेत्र में काम कर रहे कई एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए बैटरी पर जीएस्टी भी कम करेगी।

विस्तार और एलआई-आयन सेल्स के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली आयातित मशीनरी पर सीमा शुल्क को हटाने से लागत में कमी आएगी। आगे बढ़ते हुए, हम निश्चित हैं कि सरकार बैटरी पैक निर्माताओं के लिए एक पीएलआई योजना लाने पर भी विचार करेगी और ईवी क्षेत्र में काम कर रहे कई एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए बैटरी पर जीएस्टी भी कम करेगी।

समर्थ कोचर, प्रमुख एलआई-आयन बैटरी निर्माता ट्रेन्डके के संस्थापक और सीईओ 'यह बजट अब तक के सबसे अच्छे बजटों में से एक है, सही मायने में समावेशी है और समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करता है। यह भारत की कहानी के वाहक के रूप में भारत के 1.4 बिलियन लोगों को सशक्त बनाता है।

अनिल अग्रवाल, चेयरमैन, वेदांता लिमिटेड 'भूषण में दी गई लंबी अवधि की दृष्टि के साथ-साथ पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में वृद्धि, स्टार्ट-अप और एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन, हरित उर्जा, के लिए कम कर जैसी कई प्रगतिशील घोषणाओं के लिए बधाई देता हूँ। इस बजट मध्यम वर्ग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत होगी।

अनिल अग्रवाल, चेयरमैन, वेदांता लिमिटेड वर्ष 2023-24 का आम बजट अभूतपूर्व: जैन

कृषि, व्यापार-उद्योग और लघु उद्योग (रेहडी-पट्टरी) के लिहाज से मोदी सरकार का वर्ष, 2023-24 का आम बजट अभूतपूर्व है। एमएसएमई के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीताराम की ओर से महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत देने का ऐलान किया है। इसके तहत वित्त मंत्री ने कहा कि संविदागत विवादों के निपटान के लिए सैद्धिक्त समाधान योजना लाई जाएगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए केंद्र सरकार 9000 करोड़ रुपये का आवंटन करेगी। बजट में 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई को टैक्स में छूट दी गई है। इस बजट में देशभर के करीब 6 करोड़ छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देशभर के एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। नई स्कीम के तहत यह लोन 1 फीसदी कम ब्याज पर मिलेगा। बैंक आसानी से लोन दें, इसके लिए सरकार गारंटर के तौर पर काम करेगी। वित्त मंत्री ने एमएसएमई को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि जिन एमएसएमई का सालाना टर्नओवर 3 करोड़ तक हैं, उन्हें कर छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 75 लाख कमने वाले प्रोफेशनल को भी कर में छूट दी जाएगी। सरकार ने आयकर स्लैब में बदलाव किए हैं। जो स्वागत योग्य हैं। मिडिल क्लास स्यासकर नौकरी-पेशा वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। इसके तहत सालाना 7 लाख रुपये तक आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने बजट में गरीबों का भी खास ध्यान रखा है। गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना को सरकार ने एक वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। मोटे अनाजों के लिए बजट प्रावधान और कृषि ऋण लक्ष्य को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाना स्वागत योग्य है।

विजय प्रकाश जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम)

केंद्रीय बजट बहुत अच्छा है। बजट से हमारे कर्मचारियों को भी काफी राहत मिलेगी। बचत करने वालों को भी इसमें सुविधाएं मिलेगी। बजट से टैक्स की लिमिट 7 लाख बढ़ाए जाने से कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। मेजर हरजिंदर सिंह जोंजुआ, डायरेक्टर, जोंजुआ एयर प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली, पंजाब

जाता है, यह भी उचित है। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को अधिक लाभ हुआ है। एमएसएमई ने माना है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करेगा और हमारे एफएम ने टर्नओवर की सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है, यह भी बेहतरीन है।

मितेश गांधी, सीएमडी, माहिका कैमिकल्स, गुजरात 'हमारे देश के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एफएम ने मोबाइल पर ड्यूटी काम कर दी है और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों में 2.5 फीसदी की वृद्धि की है। कुल मिलाकर वर्तमान बजट हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और हमारे बाजारों को समर्थन देने में मदद करेगा।

मितेश गांधी, सीएमडी, माहिका कैमिकल्स, गुजरात 'टैक्स की लिमिट बढ़ाए जाने से कर्मियों को राहत:जोंजुआ केंद्रीय बजट बहुत अच्छा है। बजट से हमारे कर्मचारियों को भी काफी राहत मिलेगी। बचत करने वालों को भी इसमें सुविधाएं मिलेगी। बजट से टैक्स की लिमिट 7 लाख बढ़ाए जाने से कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। मेजर हरजिंदर सिंह जोंजुआ, डायरेक्टर, जोंजुआ एयर प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली, पंजाब

अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विकास प्रेरक: होलानी: केंद्रीय बजट बहुत बढ़िया है। अर्थव्यवस्था के दृष्टि से देखें तो है विकास प्रेरक है। आमजन के लिए भी बजट में 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख टैक्स में छूट देकर राहत दी है। ओवरऑल टैक्स सीमा बढ़ाकर सबको राहत दी है। बजट में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलकर कई स्कीम लागू करने की घोषणा की है।

-सीए अशोक होलानी, होलानी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड

ललित कुमार वसोया प्रबंध निदेशक, श्रीराम प्रोटीन्स लिमिटेड, राजकोट, गुजरात

केंद्रीय बजट अछा और प्रगतिशील हैं: मोहन गुरनानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामजी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत योग्य है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट अच्छा और प्रगतिशील है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में एमएसएमई क्षेत्र को राहत दी है और एमएसएमई क्षेत्र के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कोविड के प्रभाव के बाद तनाव से जुड़ रहा था। एमएसएमई के लिए कई क्रेडिट गारंटी योजना से क्रेडिट की लागत कम होने की उम्मीद है। प्रोफेशनल्स की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई है, जो वर्तमान समय की जरूरत थी। लंबे समय से प्रत्यक्ष कराराज में रहते से उन छोटे कर्षाताओं को राहत मिलेगी, जो महंगाई की मार झेल रहे थे। उच्च आय वर्ग के लिए अधिभार में कमी भी एक स्वागत योग्य संकेत है, जिससे संपत्ति बनाने में मदद मिलेगी। बजट में चीनी उद्योग को समय पर दी गई राहत किसानों को सीधे तौर पर मदद करेगी। अगर जीएस्टी के तहत उम्मीद से ज्यादा राजस्व संग्रह को देखते हुए जीएस्टी में कुछ राहत दी जाती तो बेहतर होता। कुल मिलाकर बजट अभिव्योक्तुमुखी बजट है, जो देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

ललित कुमार वसोया प्रबंध निदेशक, श्रीराम प्रोटीन्स लिमिटेड, राजकोट, गुजरात 'केंद्रीय बजट अछा और प्रगतिशील हैं: मोहन गुरनानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामजी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत योग्य है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट अच्छा और प्रगतिशील है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में एमएसएमई क्षेत्र को राहत दी है और एमएसएमई क्षेत्र के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कोविड के प्रभाव के बाद तनाव से जुड़ रहा था। एमएसएमई के लिए कई क्रेडिट गारंटी योजना से क्रेडिट की लागत कम होने की उम्मीद है। प्रोफेशनल्स की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई है, जो वर्तमान समय की जरूरत थी। लंबे समय से प्रत्यक्ष कराराज में रहते से उन छोटे कर्षाताओं को राहत मिलेगी, जो महंगाई की मार झेल रहे थे। उच्च आय वर्ग के लिए अधिभार में कमी भी एक स्वागत योग्य संकेत है, जिससे संपत्ति बनाने में मदद मिलेगी। बजट में चीनी उद्योग को समय पर दी गई राहत किसानों को सीधे तौर पर मदद करेगी। अगर जीएस्टी के तहत उम्मीद से ज्यादा राजस्व संग्रह को देखते हुए जीएस्टी में कुछ राहत दी जाती तो बेहतर होता। कुल मिलाकर बजट अभिव्योक्तुमुखी बजट है, जो देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड ने घोषित किए वित्तीय परिणाम, बिक्री और लाभ में उल्लेखनीय बढ़त

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। नई दिल्ली आधारित प्रमुख ऑटो कंपोनेंट और इक्विपमेंट निर्माता कंपनी स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही और नौमाही के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। उक्त अवधि में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन: कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अनुसार कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 122.47 करोड़ रुपये के मुकाबले 208.45 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। उक्त तिमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 5.46 करोड़ रुपये के कर पश्चात शुद्ध लाभ के मुकाबले 13.91 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2022 को समाप्त नौमाही में गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 342.51 करोड़ रुपये के मुकाबले 556.21 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। उक्त नौमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 18.65 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ के मुकाबले 40.09 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। उक्त अवधि में कंपनी ने 11.13 रुपये का ईपीएस अर्जित किया है।

आर्टिमीस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड ने घोषित किए वित्तीय परिणाम, बिक्री और लाभ में वृद्धि दर्ज

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। नई दिल्ली में आर्टिमीस हॉस्पिटल संचालन के साथ विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं सुहैया कराने वाली कंपनी आर्टिमीस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही और नौमाही के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। उक्त अवधि में कंपनी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन: कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अनुसार कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 145.04 करोड़ रुपये के मुकाबले 188.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। उक्त तिमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 6.36 करोड़ रुपये के कर पश्चात शुद्ध लाभ के मुकाबले 10.26 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2022 को समाप्त नौमाही में गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 408.03 करोड़ रुपये के मुकाबले 547.10 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। उक्त नौमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 18.19 करोड़ रुपये की कर पश्चात शुद्ध लाभ के मुकाबले 27.30 करोड़ रुपये की कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। उक्त अवधि में कंपनी ने 2.09 रुपये का ईपीएस अर्जित किया है।

स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड ने घोषित किए वित्तीय परिणाम, बिक्री और लाभ में दर्ज हुई बढ़त

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। नई दिल्ली आधारित कंज्यूमर गुड्स बिक्री क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन: स्टैंडलोन बैलेंस शीट के अनुसार कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 17.78 करोड़ रुपये के मुकाबले 35.99 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। उक्त तिमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 1.01 करोड़ रुपये के कर पश्चात शुद्ध लाभ के मुकाबले 1.37 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2022 को समाप्त नौमाही में गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 33.63 करोड़ रुपये के मुकाबले 85.18 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। उक्त नौमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 1.51 करोड़ रुपये की कर पश्चात शुद्ध लाभ के मुकाबले 3.82 करोड़ रुपये की कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। उक्त अवधि में कंपनी ने 0.19 रुपये का ईपीएस अर्जित किया है।

ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड ने घोषित किए वित्तीय परिणाम

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। नई दिल्ली आधारित शुगर निर्माण एवं पावर जनरेशन क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी की निर्माण इकाई बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन: कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 34.70 करोड़ रुपये के मुकाबले 55.61 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। उक्त तिमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 2.88 करोड़ रुपये की कर पश्चात शुद्ध हानि के मुकाबले 12.59 लाख रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2022 को समाप्त नौमाही में गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 111.59 करोड़ रुपये के मुकाबले 142.21 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। उक्त नौमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 9.18 करोड़ रुपये की कर पश्चात शुद्ध हानि के मुकाबले 8.97 करोड़ रुपये की कर पश्चात शुद्ध हानि अर्जित की है। गौरतलब है कि कंपनी का शेयर वर्तमान में करीब रुपये 4 प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी की मार्केट कैप मात्र 4.98 करोड़ रुपये ही है।

INANI MARBLES & INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L14101RJ1994PLC008930)
Registered Office: Arajali No. 1312, Udaipur- Bhilwara Highway, Near Mataji Ki Pandoli Chittorgarh, Rajasthan-312001
E-mail: inanimarble@gmail.com Website: www.inanimarbles.com

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Company will be held on Saturday, 25th February, 2023 at 03:00 P.M. at ARAJALI No. 1312 Udaipur-Bhilwara Highway Near Mataji Ki Pandoli Chittorgarh (Raj.)- 312001, to transact the business set out in the Notice of Meeting.
In Compliance with the relevant MCA and SEBI circulars the notice of EGM is being sent to members in electronic form to the Emails registered with their Depository Participants. For members whose Email IDs are not registered we request shareholders to update their email ids with the depositories/ RTA as soon as possible. The Notice may also be accessed on the website of the Company at www.inanimarbles.com and website of Central Depository Service (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com and at the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com
The Members who have not yet registered or updated their email ID are requested to register their email addresses, with their Depository Participants. For members holding shares in physical mode, please provide necessary details like folio no., name of shareholder(s) and email addresses at investor@ankitonline.com. Pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended) (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Company is pleased to provide its shareholders the facility to cast their vote on the resolutions set forth in the Notice through electronic voting system ("REMOTE E-VOTING") of Central Depository Service (India) Limited (CDSL). The Detailed procedure/instructions for remote e-voting are contained in the notice of the EGM. In this regard, the members are further notified that:
a) A person whose name is recorded in the register of the members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 18th February, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and voting at the EGM.
b) The remote e-voting period commences on Wednesday, 22nd February, 2023 (9:00 a.m.) and ends on Friday, 24th February, 2023 (5:00 p.m.).
c) The voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 24th February, 2023.
d) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM can attend the EGM but shall not be entitled voting at the EGM.
e) CS Anil Kumar Somani, Practising Company Secretary has been appointed as scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner.
In case of any queries or grievances regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual which is available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com, helpdesk number-1800-200-5533
Date: 01.02.2023
For Inani Marbles & Industries Limited
Sd/-
Madhu Bala Sharma
Company Secretary